



निगरानी क्र. 911-III-15

राजस्व श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर मोग्रो केम्प इन्दौर



1४ प्रबोध कुमार पिता सायमन आदिवासी बारेला निवासी महु जिला इंदौर मोग्रो

2४ राकेश कुमार पिता सायमन आदिवासी बारेला निवासी महु जिला इंदौर मोग्रो

3४ अमित कुमार पिता सायमन आदिवासी बारेला निवासी महु जिला इंदौर मोग्रो
Adv. श्री मोहन - पारिवारिक कानून/अभिभावक द्वारा दिनांक 17/04/15

4४ प्रभा पिता सायमन आदिवासी बारेला निवासी इंदौर जिला इंदौर
1162
17-04-15

5४ रजना पिता सायमन आदिवासी बारेला निवासी जयपुर हाउस महु जिला इंदौर

6४ मालिनी पिता सायमन आदिवासी बारेला निवासी महु जिला इंदौर
27-4-15

7४ श्वेता पिता सायमन आदिवासी बारेला निवासी महु जिला इंदौर .. रिक्वीजनकर्ता विरुद्ध

1४ काशीराम पिता मांगीलाल काक्षी निवासी बडवानी चौदशों मोहल्ला बडवानी

2४ प्रेमसिंह पिता रजान पटेल निवासी साईनाथ कॉलोनी बडवानी .. प्रतिप्राथीगण

रिक्वीजन याचिका अंतर्गत धारा 50 मोग्रो भू राजस्व संहिता

रिक्वीजनकर्ता की ओर से सादर निवेदन है कि -

1. यह कि रिक्वीजनकर्ता के द्वारा यह रिक्वीजन अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय कलेक्टर बडवानी के द्वारा अपील

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a signature that appears to be 'M. Sharm' and the date '22/4/15'.

Handwritten note: 'Copy sent to Mr. ... 40 ... 1/15/15'

Handwritten signature at the bottom left: 'मोहन कुमार'

Handwritten signature at the bottom center: 'शक्ति किराडिया'

Handwritten signature at the bottom center: 'अमित किराडिया'

Handwritten signature at the bottom right: 'Bhai 2'

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

जिला बडवानी

प्रकरण क्रमांक निगरानी 911-तीन/2015
प्रबोध कुमार आदि

विरुद्ध

काशीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-5-2015	<p>आवेदक अभिभाषक एवं केवीयेटकर्ता अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर बडवानी के प्रकरण क्रमांक 30/अ-23/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 07-02-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>3/ कलेक्टर के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने आवेदकों की से प्रस्तुत निगरानी को विलंब के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उसे समयबाधित मानते हुये अग्राह्य किया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में विस्तार से विलम्ब के संबंध में विवेचना कर आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय के अतिरिक्त इस न्यायालय में भी आवेदकों द्वारा निगरानी 05 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में आवेदकों ने निगरानी इस न्यायालय में भी अवधि बाह्य प्रस्तुत की है। फलस्वरूप यह निगरानी अवधि बाह्य एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	

(डॉ० मधु खरे)
सदस्य